भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 785

(25 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत बजट आवंटन

785. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और व्यय किए गए कुल बजट का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पिछले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत कार्य संबधित मांग को पूरा करने के लिए बजट आवंटन पर्याप्त रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों अर्थात 2029-30 तक के लिए इस योजना हेतु परिव्यय में वृद्धि की मांग की है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत बजट अनुमान चरण , संशोधित अनुमान चरण के तहत निधियों के आवंटन और जारी निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी निधि
1	2020-21	61500.00	111500.00	1,11,170.86
2	2021-22	73000.00	98000.00	98,467.85
3	2022-23	73000.00	89400.00	90,810.99
4	2023-24	60000.00	86000.00	89,268.30
5	2024-25	86000.00	86000.00	85,838.76

चूँकि, महात्मा गांधी नरेगा योजना एक माँग-आधारित मजदूरी-रोजगार योजना है , इसलिए बजट परिव्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में रोजगार की प्रत्याशित माँग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह मंत्रालय माँग के आधार पर निधियों की आवश्यकताओं का नियमित आकलन करता है और ज़मीनी स्तर पर काम की माँग को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की माँग करता है। यह उल्लेख किया जाता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में (22.07.2025 तक) 99.79% पात्र ग्रामीण परिवारों को उनकी माँग के अनुरूप रोजगार का पेशकश किया गया है।

यहाँ, यह भी ध्यान देने योग्य है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹86,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है , जो इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक बजट अनुमान (बीई) स्तर पर इसके लिए किया गया अब तक का सबसे अधिक आवंटन था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सरकार ने योजना के लिए निरंतर सहायता सुनिश्चित करते हुए इस आवंटन को ₹86,000 करोड़ बनाए रखा है।

(ग): भारत सरकार रोजगार के सतत अवसरों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना को मजबूत करने और सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।